



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 19, 2012/ज्येष्ठ 29, 1934

No. 145]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 19, 2012/JYAISTHA 29, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2012

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'मेटा फिनायलीन डायामाइन' (एमपीडीए) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत ।

सं. 14/4/2012-डीजीएडी.— यतः समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे एतदपश्चात पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) के अनुसार चीन जन.गण. (जिसे एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेटा फिनायलीन डायामाइन (एमपीडीए) (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए मै0 आरती इण्डस्ट्री लिमिटेड, मुंबई (जिसे एतदपश्चात आवेदक कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है और पाटनरोधी जांच शुरु करने एवं पाटनरोधी उपाय अधिरोपित करने का अनुरोध किया है।

## विचाराधीन उत्पाद

2. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद 'मेटा फिनायलीन डायामाइन' (एमपीडीए) है। विचाराधीन उत्पाद को एमपीडीए भी कहा जाता है । वाणिज्यिक रूप से इसे एमपीडी या

एमपीडीए भी कहा जाता है। सामान्य(कक्ष) स्थितियों में यह रंगहीन या सफेद रंग का ठोस होता है जो भण्डारण करने पर हवा में लाल, बैंगनी (गहरे रंग का) हो जाता है। मेटा फिनायलीन डायामाइन मेटा स्थिति में एक दूसरे के संबंध में बेन्जीन आभा (टिंग) युक्त दो अमीनो समूहों से संबद्ध होता है। यह ०-फिनायलीन डायामाइन (आर्थो फिनायलीन डायामाइन) और पी-फिनायलीन डायामाइन (पैरा फिनायलीन डायामाइन) का एक आइजोमर है। विचाराधीन उत्पाद के कोई ज्ञात ग्रेड नहीं हैं। मेटा फिनायलीन डायामाइन रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है।

एमपीडीए रंगों, इंजीनियरिंग पालीमर, ऐरामिड फाइबर के विनिर्माण के लिए मध्यवर्ती रसायन के रूप में कार्य करता है और इसका फोटोग्राफी एवं चिकित्सा अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है।

3. 'मेटा फिनायलीन डायामाइन' को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम में अध्याय 29 के अन्तर्गत उपशीर्ष सं० 29215120 पर वर्गीकृत किया गया है। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतक है और यह इस जाँच के दायरे में किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

### घरेलू समान वस्तु

4. आवेदक ने दावा किया है कि सम्बद्ध वस्तुएं, जिनका भारत में पाटन किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समरूप हैं। पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित सम्बद्ध वस्तुओं के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्यो या अन्तिम प्रयोग में कोई ज्ञात अन्तर नहीं है। दोनों, तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और अतः उन्हें पाटनरोधी नियमों के अन्तर्गत 'समान वस्तु' के रूप में माना जाए।

5. इस प्रकार, आवेदक द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु को इस जाँच के प्रयोजनार्थ पाटनरोधी नियमावली के आशय के अन्तर्गत सम्बद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु के रूप में माना जा रहा है।

### घरेलू उद्योग और 'स्थिति'

6. यह आवेदन मै० आरती इण्डस्ट्री लिमि०, मुंबई द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया है। यह दावा किया गया है कि मै० आरती इण्डस्ट्री लिमि० सम्बद्ध वस्तु का भारत में एकमात्र उत्पादक है। अतः आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) में उल्लिखित अपेक्षाओं को संतुष्ट करता है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने यह निश्चय किया है कि यह

आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) में उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करता है और आवेदक को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के आशय के अन्तर्गत 'घरेलू उद्योग' के रूप में माना जा रहा है।

### शामिल देश

7. इस जाँच में शामिल देश चीन जन.गण. है (जिसका एतदपश्चात् सम्बद्ध देश के रूप में भी उल्लेख किया गया है)।

### सामान्य मूल्य

8. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना जाना चाहिए। आवेदक ने पुनः दावा किया है कि उनके द्वारा सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था की कीमत निर्मित मूल्य के आधार पर इस कारण नहीं किया जा सकता है कि संगत जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त यह उल्लेख किया गया कि सम्बद्ध वस्तु के चीन जन.गण., यूएसए, कनाडा और भारत के सिवाय अन्य कोई ज्ञात उत्पादक नहीं हैं। विचाराधीन उत्पाद की यूएसए या कनाडा में लागत या कीमत के संबंध में जानकारी के अभाव में, इस जाँच की शुरुआत करने के उद्देश्य के लिए सामान्य मूल्य दावों का आकलन भारत में विधिवत समायोजित, भुगतान योग्य कीमत पर आधारित उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है।

9. प्राधिकारी ने, इस जाँच की शुरुआत करने के प्रयोजन के लिए, प्रथम दृष्टया सम्बद्ध देश में सम्बद्ध वस्तु के विनिर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

### निर्यात कीमत

10. आवेदक ने डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है। अद्यतन अवधि अर्थात् सितम्बर, 2011 तक के लिए उपलब्ध डीजीसीआई एंड एस आंकड़ों पर विचार किया गया है। निवल फैक्टरी-बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्री भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के अनुसार कीमत समायोजन की प्रथम दृष्टया अनुमति दी गई है।

### पाटन मार्जिन

11. इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर यह पाया गया कि सम्बद्ध वस्तु की सम्बद्ध देश में सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से अत्यधिक ज्यादा है।

जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि सम्बद्ध देश में उत्पादित या सम्बद्ध देश से निर्यातित सम्बद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है जिससे पाटनरोधी जाँच शुरू करना न्यायोचित है।

### 'क्षति' और कारणात्मक सम्बन्ध

12. आवेदक ने पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में कथित पाटन, कीमत में कटौती, कीमत हास और लाभदायकता, लगाई गई पूँजी पर आय और घरेलू उद्योग के नकदी प्रवाह में कमी के कारण होने वाली 'क्षति' के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

13. सम्बद्ध देश से पाटित आयातों से घरेलू उद्योग द्वारा सहन की जा रही 'क्षति' के पर्याप्त साक्ष्य हैं जिससे पाटनरोधी नियमावली के अन्तर्गत पाटनरोधी जाँच शुरू करना न्यायोचित ठहरता है।

### पाटनरोधी जाँच की शुरुआत

14. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी यह पाते हैं कि सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को 'क्षति' और पाटन तथा 'क्षति' के बीच कारणात्मक सम्बन्ध के पर्याप्त साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जाँच शुरू करने को न्यायोचित ठहराते हैं। तदुसार, प्राधिकारी कथित पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली 'क्षति' के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अन्तर्गत कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी डिग्री और उसके प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी उपाय की राशि, जो यदि वसूली जाती तो, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होती, की सिफारिश करने के लिए जाँच शुरू करते हैं।

### जाँच अवधि

15. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि 1 अक्टूबर, 2010 से 31 दिसम्बर, 2011 (15 माह) है। तथापि क्षति विश्लेषण में अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009, अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010, अप्रैल 2010 से मार्च, 2011 और जाँच की अवधि शामिल होगी।

### सूचना प्रस्तुत करना

16. सम्बद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों और भारत स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत के ज्ञात आयातकों और संबंधित प्रयोक्ताओं एवं घरेलू उद्योग को निर्धारित स्वरूप एवं ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने तथा अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से

लिखा जा रहा है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी अधोलिखित समय सीमा के अन्तर्गत इस जाँच से संगत जानकारी निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत कर सकता है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी  
पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
कमरा सं० 240, उद्योग भवन,  
नई दिल्ली-110107

फोन: 00-91-11-23061377/23063418(फैक्स)

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित ढंग से जाँच से संगत निवेदन कर सकता है।

#### समय सीमा

18. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु किया गया कोई भी अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर पहुँच जाना चाहिए। यदि निर्धारित समयावधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे प्रस्तुत मामले में अपने हित (हित की प्रवृत्ति सहित) के बारे में सूचित करें और अपनी-अपनी प्रश्नावलियों के प्रत्युत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने अथवा नहीं जारी रखने की आवश्यकता के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियाँ इस जाँच के शुरू होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के अन्दर प्रस्तुत करें।

#### गोपनीय आधार पर उत्तर प्रस्तुत करना

20. प्रश्नावली के उत्तर/निवेदन के किसी भाग पर गोपनीयता का दावा किए जाने के मामले में इसे दो अलग-अलग भागों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए; (क) गोपनीयता के रूप में चिन्हित (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि) और (ख) दूसरा भाग अगोपनीय के रूप में चिन्हित (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि)। उपलब्ध कराई गई समस्त सूचना में प्रत्येक पृष्ठ पर ऊपर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" लिखा जाना चाहिए।

21. बिना चिह्न के उपलब्ध कराई गई सूचना अगोपनीय समझी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी किसी भी अगोपनीय सूचना के निरीक्षण की अनुमति प्रदान करने हेतु स्वतंत्र होंगे। गोपनीय पाठ और अगोपनीय पाठ दोनों की दो (2) पृथक प्रतियाँ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

22. जिस सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है उस सूचना के आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराई गई सूचना के साथ कारणों का ब्यौरा प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती है एवं/अथवा ऐसी सूचना का संक्षेप क्यों संभव नहीं है।

23. अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए और जिस सूचना के बारे में गोपनीयता का दावा किया गया हो उसे अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा मिटाया/संक्षेपित किया जाना चाहिए। अगोपनीय सारांश में दिया गया ब्यौरा पर्याप्त होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय-वस्तु आसानी से समझी जा सके। तथापि अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना संक्षेपण योग्य नहीं है और संक्षेपण संभव क्यों नहीं है, इसके कारणों का ब्यौरा निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

24. प्रस्तुत की गई सूचना की जाँच के उपरांत प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता हेतु अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्य अथवा सारांश रूप इसके प्रकटीकरण को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं।

25. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में दिए गए कारण के ब्यौरे के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को निर्दिष्ट प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं लेंगे। प्राधिकारी, प्रदत्त सूचना से संतुष्ट होने और गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार कर लेने पर ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किए बिना किसी भी पक्षकार के समक्ष इसे प्रकट नहीं करेंगे।

### सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

26. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

**असहयोग**

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जाँच में बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th June, 2012

**Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of 'Meta Phenylene Diamine' (MPDA) originating in or exported from China PR.**

**No. 14/4/2012-DGAD.**— Whereas M/s Aarti Industry Ltd., Mumbai (hereinafter referred to as the Applicant ) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time, (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter referred to as the AD Rules), alleging dumping of '*Meta Phenylene Diamine*' (MPDA) (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country) and has requested for initiation of anti- dumping investigation and levy of anti dumping measures.

**Product under consideration**

2. The product under consideration in the present application is 'Meta Phenylene Diamine' (MPDA). The product under consideration is also referred to as MPDA. Commercially, it is also called MPD or MPDA. Under normal (room) conditions, it is a colourless or white colour solid, which tends to turn red, purple (dark colour) in air, on storage. Meta Phenylene Diamine has two amino groups attached to a Benzene ring, at Meta position, with respect to each other. It is an isomer of o- Phenylene Diamine (Ortho Phenylene Diamine) and p- Phenylene Diamine (Para Phenylene Diamine). There are no known grades of the product under consideration. Meta Phenylene Diamine functions as a chemical intermediate.

MPDA is a chemical intermediate used for manufacturing dyes, engineering polymer, aramid fiber and in photography & medical applications.

3. 'Meta Phenylene Diamine' is classified under Chapter 29 at subheading no. 29215120 in the Customs Tariff Act . However, Customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

**Domestic Like Article**

4. The applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known difference either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the AD Rules.

5. Thus, the subject goods produced by the Applicant are being treated as like article to the product under consideration imported from the subject country within the meaning of the AD Rules for the purpose of this investigation.

**Domestic industry & 'Standing'**

6. The Application has been filed by M/s Aarti Industry Ltd., Mumbai on behalf of the domestic industry. It has been claimed that M/s Aarti Industry Ltd. is the sole producer of the subject goods in India. The application, therefore, satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules. Thus, the Authority has determined that the application satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules and the Applicant is being treated as 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules.

**Country involved**

7. The country involved in the present investigation is China PR (hereinafter also referred to as the subject country).

**Normal value**

8. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy country. The applicant has further claimed that normal value could not be determined by them on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available. It has been further stated that there are no other known producers of the subject goods except in China PR, USA, Canada and India. In the absence of information with regards to cost or price of the product under consideration in USA or Canada; for the purposes of this initiation, the normal value claims has been estimated on the basis of cost of production method based on the price payable in India, duly adjusted.

9. The Authority has prima-facie considered the normal value of subject goods in subject country on the basis of constructed value, for the purpose of the initiation of this investigation.

**Export price**

10. The applicant has claimed export prices on the basis of data obtained from DGCI&S. The DGCI&S data has been taken into consideration for the latest available period that is till September 2011. Price adjustments have been prima facie allowed on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses and bank charges to arrive at the net ex-factory export price.



**Dumping margin**

11. Based on the normal value and export price so determined, it is found that the normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the net export prices, prima-facie, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country are being dumped, to justify initiation of an antidumping investigation.

**'Injury' and Causal link**

12. The applicant has furnished evidence regarding the 'injury' having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports, price undercutting, price suppression and decline in profitability, return on capital employed and cash flow for the domestic industry.

13. There is sufficient evidence of the 'injury' being suffered by the domestic industry caused by the dumped imports from the subject country to justify initiation of an antidumping investigation in terms of the AD Rules.

**Initiation of Anti Dumping Investigation**

14. In view of the foregoing, the Authority finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods from the subject country, 'injury' to the domestic industry and causal link between the dumping and 'injury' exists to justify initiation of an anti-dumping investigation. Accordingly, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent 'injury' to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping measure, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**Period of investigation**

15. The period of investigation considered in the present investigation is 1<sup>st</sup> October 2010 to 31<sup>st</sup> December 2011 (15 Months). However, the injury analysis would cover the periods April 2008-March 2009, April 2009-March 2010, April 2010-March 2011 and the POI.

**Submission of information**

16. The known exporters in the subject country and its Government through their Embassy in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

The Designated Authority,  
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,  
Ministry of Commerce & Industry,  
Department of Commerce  
Room No.240, Udyog Bhawan,  
New Delhi -110107. Phone: 00-91-11-23061377/23063418(fax)

2204 GE/12-3

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

#### **Time Limit**

18. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire's responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the AD measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

#### **Submission of information on confidential basis**

20. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

21. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

22. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Inspection of public file**

26. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

**Non-cooperation**

27. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority